

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सचिव-सह-वाणिज्य कर आयुक्त

बनाम

मेसर्स गंगोत्री आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड एवं अन्य

2015 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2726

में

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 454

06 अगस्त 2024

(माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायाधीश श्री पार्थ सारथी)

विचार के लिए मुद्दा

क्या औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 (जिसे आगे 'नीति' कहा जाएगा) में प्रवेश कर (ईटी) और केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के 80% के साथ-साथ मूल्य वर्धित कर (वैट) की प्रतिपूर्ति के माध्यम से प्रोत्साहन का प्रावधान था?

हेडनोट्स

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 - प्रतिपूर्ति का दायरा - बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के खंड 2(vi) के अंतर्गत प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन, सरकार के खाते में भुगतान किए गए वैट तक सीमित है और प्रवेश कर या केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) तक विस्तारित नहीं है।

प्रवेश कर और वैट - अलग-अलग वैधानिक शुल्क प्रवेश कर और वैट अलग-अलग कानूनों के तहत लगाए जाते हैं। नीति के तहत प्रवेश कर के लिए वैट प्रतिपूर्ति उपलब्ध नहीं है, हालाँकि प्रवेश कर को वैट देयता के तहत एक सेट-ऑफ के रूप में समायोजित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण खंड और अनुलग्नक III - व्याख्यात्मक सीमाएँ खंड 2(vi) का स्पष्टीकरण और अनुलग्नक III (पासबुक) की प्रविष्टियाँ प्रवेश कर या सीएसटी को प्रोत्साहन का दायरा नहीं बढ़ाती हैं। ये दस्तावेज़ जुर्माने या निर्धारित कर अंतर पर सब्सिडी को रोकने के लिए हैं, न कि नीति के दायरे को बढ़ाने के लिए।

वचन-विराम - जहाँ नीति स्पष्ट है वहाँ लागू नहीं वचन-विराम के सिद्धांत का उपयोग वहाँ नहीं किया जा सकता जहाँ नीति की स्पष्ट शर्तें लाभ के दायरे को सीमित करती हैं।

कराधान प्रोत्साहन नीतियों की व्याख्या - शाब्दिक नियम लागू राजकोषीय कानूनों और प्रोत्साहन योजनाओं के मामले में, जब तक अस्पष्टता स्पष्ट न हो, शाब्दिक व्याख्या ही मान्य होती है।

न्याय दृष्टान्त**अधिनियमों की सूची**

बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005; केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956; बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, उपयोग या बिक्री हेतु वस्तुओं के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993; बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 (धारा 2(vi)), भारत का संविधान

मुख्य शब्दों की सूची

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति; प्रवेश कर; वैट प्रतिपूर्ति; सेट-ऑफ; केंद्रीय बिक्री कर; राजकोषीय व्याख्या; वचनबद्धता निषेध; स्पष्टीकरण खंड

प्रकरण से उत्पन्न

सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2726/2015

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री विकास कुमार, एस.सी. - 11

श्री रेवती कांत रमन (ए.सी. टू एस.सी. - 11)

प्रतिवादी/ओं की ओर से: श्री पी. के. शाही (एजी)

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: रवि राज, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2015 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2726
में
2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 454

- =====
1. बिहार सरकार के वाणिज्यिक कर सचिव-सह-आयुक्त, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
 2. वाणिज्यिक करों के उपायुक्त, उत्तर मंडल के प्रभारी, पटना।

.. ... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. मेसर्स गंगोत्री आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विधिवत पंजीकृत एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 307, आशियाना टावर्स, एग्जिबिशन रोड, पटना में है, अपने एक निदेशक संजीव कुमार चौधरी, पिता - स्वर्गीय शिव भगवान चौधरी, निवासी - 7 वीं मंजिल, कलारुका निवास, दक्षिण गांधी मैदान, थाना- गांधी मैदान, जिला-पटना - 800001 के माध्यम से।
2. बिहार राज्य अपने मुख्य सचिव, बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय, पटना के माध्यम से।
3. विकास आयुक्त, बिहार सरकार का मुख्य सचिवालय, पटना।
4. औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार सरकार विकास भवन, बेली रोड, पटना।
5. निदेशक (तकनीकी), उद्योग विभाग, बिहार सरकार विकास भवन, बेली रोड, पटना।
6. महाप्रबंधक, जिला, उद्योग, केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलिपुत्र कोलोनी, पाटलिपुत्र, पटना।

... ... उत्तरदाता/गण

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री विकास कुमार, एस. सी.-11 श्री रेवती कांत रमन (एस. सी.-11 के ए. सी.)
उत्तरदाता/ओं के लिए	:	श्री पी. के. शाही (एजी)

=====

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश
 और
 माननीय न्यायाधीश श्री पार्थ सारथी
 सी.ए.वी. निर्णय
 (प्रति: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख: 06-08-2024

अपील में उठाया गया मुद्दा एक संकीर्ण दायरे में है, कि क्या औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 (जिसे इसके बाद 'नीति' के रूप में संदर्भित किया गया है) में मूल्य वर्धित कर (वैट) के साथ प्रवेश कर (ईटी) और केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के 80 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान था।

2. विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मुद्दे को तीन आधारों पर करदाता, रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाया। पहला नीति के खंड 2 (6) के स्पष्टीकरण पर; जिसमें 'मूल्य वर्धित कर पर सब्सिडी/प्रोत्साहन' का प्रावधान है, यह निर्धारित करते हुए कि प्रोत्साहन जुर्माना के रूप में लगाई गई राशि पर देय नहीं होगा; साथ ही केंद्रीय बिक्री कर (सी. एस. टी.)/बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (वी. ए. टी. अधिनियम) और बिहार प्रवेश कर अधिनियम (ई. टी. अधिनियम) के तहत निर्धारित और स्वीकार की गई कर राशि के बीच के अंतर का भी भुगतान किया जाएगा। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रोत्साहन तीनों करों पर देय होगा केवल वैट पर ही नहीं। अगला तर्क यह था कि नीति के अनुलग्नक-III में; जो प्रोत्साहन का दावा करने के उद्देश्य से रखी जाने वाली पास बुक है, वहां वैट, सी. एस. टी. और ई. टी. अधिनियमों के तहत स्वीकार की गई कर की राशि को दिखाने का प्रावधान है; जो विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, इसके स्पष्ट अर्थ को ध्यान में रखते हुए अटकलों या निर्धारण या निर्णय के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है कि प्रोत्साहन प्रवेश कर पर भी उपलब्ध होगा। विवरणी पर भी विचार किया गया, जो आर. टी.-3 प्रपत्र में था, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रवेश कर के माध्यम से करदाता द्वारा जमा

की गई राशि को करदाता के स्वीकृत वैट की राशि का एक अभिन्न अंग के रूप में दर्शाया गया था, जो दोनों को अविभाज्य बनाता है; उन आधारों में से अंतिम आधार जिस पर प्रोत्साहन प्रवेश कर पर भी लागू पाया गया था। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रोत्साहन की पात्रता, नीति के अनुसार भुगतान किए गए प्रवेश कर और किसी प्रावधान या खंड के नाममात्र शीर्षक को भी शामिल करती है, केवल उस चीज को बाहर करने के लिए निर्भर नहीं किया जा सकता है जो अन्यथा शामिल है। समग्र नीति और प्रयुक्त भाषा को देखते हुए, प्रवेश कर को शामिल करना स्पष्ट, असंदिग्ध और सुनिश्चित माना गया। केवल वैट के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन की बात करने वाले शीर्षक के बावजूद, मूल प्रावधान इसके विपरीत इंगित करता है; यह घोषणा थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने वचनबद्धता के सिद्धांत पर भी भरोसा किया, जहाँ तक करदाता ने नीति दस्तावेज़ में राज्य द्वारा किये गए वादे पर कार्य करते हुए नीति के अनुसार निवेश करके अपनी स्थिति बदल दी है।

3. अपीलार्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री पी.के. शाही ने नीति दस्तावेज़ के खंड 2(vi) का हवाला देते हुए कहा कि उसमें प्रयुक्त स्पष्ट और सरल भाषा से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्रोत्साहन वैट तक ही सीमित था। स्पष्टीकरण में सी. एस. टी. और प्रवेश कर के संदर्भ की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है, जो प्रोत्साहन देने वाले मूल खंड के विपरीत होगा। स्पष्टीकरण केवल यह दर्शाता है कि सी. एस. टी., वैट और प्रवेश कर के रूप में निर्धारित कर का अंतर, जो स्वीकृत/स्वीकृत कर से अधिक है, प्रोत्साहन के रूप में प्रतिपूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं होगा। 'स्वीकृत' और 'मूल्यांकित' शब्दों का उपयोग वैट व्यवस्था के संदर्भ में किया गया है जिसमें निर्धारित रिटर्न दाखिल करके स्व-मूल्यांकन किया जाता है, जबकि वैट अधिनियम के तहत मूल्यांकन प्राधिकरण को दाखिल किए गए विवरणी की जांच के बाद पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार है, जो कि 'मूल्यांकित' कर होगा। विद्वान महाधिवक्ता ने इस न्यायालय के *खिचड़ी राम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य; (2009) 2 पी. एल. जे. आर. 265*, में दिए गए

खंडपीठ के निर्णय का भी हवाला दिया है, और तर्क दिया है कि यदि अंग्रेजी संस्करण में कोई अस्पष्टता है, तो हिंदी संस्करण, जो राज्य की आधिकारिक भाषा में मूल अधिसूचना है, को देखा जाना चाहिए; जिसे राज्य द्वारा बनाई गई प्रामाणिक नीति माना गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने नीति द्वारा बनाए गए प्रोत्साहन दायरे में प्रवेश कर को भी शामिल करने में स्पष्ट रूप से गलती की है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

4. उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. डी. संजय विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेशों का बचाव करना चाहते हैं। इस बात पर जोर दिया जाता है कि यह नीति स्वयं उत्पादकता बढ़ाने, राज्य में अधिक निवेश को सक्षम बनाने और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई थी। नीति की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, प्रावधान को एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए और प्रवेश कर जिसे वैट में शामिल किया गया है, को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इस बात पर जोर देने के लिए हमें नीति के माध्यम से ले जाते कि बिजली शुल्क और विलासिता कर को भी छूट दी गई थी, और यह सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने प्रोत्साहन को वैट तक सीमित कर दिया और प्रवेश कर घटक के लिए इसे अस्वीकार कर दिया। इस तर्क को और मजबूत करने के लिए कि प्रवेश कर भी प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत आता है, नीति दस्तावेज़ के अनुलग्नक-III और दाखिल किए गए विवरणी को पढ़ा जाता है।

5. शुरुआत में, हमें यह देखना होगा कि बिजली शुल्क और विलासिता कर के पहलू को नीति के तहत लाया गया है; इसका परिणाम यह नहीं है कि प्रवेश कर को भी प्रोत्साहन देने के लिए शामिल किया जा रहा है। शुरुआत में ही, हमें भी, नीति में संलग्न प्रपत्र के आधार पर तय किए जा रहे विशिष्ट प्रावधान के संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज करनी चाहिए; जो नीति के तहत प्रोत्साहन को सक्षम करने के उद्देश्य से बनाए रखी जाने वाली पास बुक है। पास बुक का एक विशिष्ट उद्देश्य है, जिसे हम थोड़ी देर बाद विस्तार से बताएंगे।

6. हमें पहले नीति के तहत विशिष्ट खंड निकालना होगा; जो कि खंड 2 (vi) है, जो

निम्नलिखित है :-

वैट पर सब्सिडी/प्रोत्साहन:

यह सुविधा लघु/बड़े/मध्यम उद्योगों के लिए उपलब्ध होगी। औद्योगिक इकाई को राज्य सरकार से एक पासबुक मिलेगी जिसमें बिहार वैट के तहत भुगतान किए गए कर का विवरण वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा परिशिष्ट-III में निर्धारित प्रपत्र में दर्ज और सत्यापित किया जाएगा। निदेशक, उद्योग सत्यापन के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत होंगे।

नई इकाइयों को दस साल की अवधि के लिए सरकार के खाते में जमा की गई स्वीकृत वैट राशि के बदले 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। अधिकतम सब्सिडी राशि निवेशित पूंजी का 300% देय है।

स्पष्टीकरण:

केंद्रीय बिक्री कर/बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 और बिहार प्रवेश कर अधिनियम के तहत जुर्माने के रूप में लगाई गई राशि और कर निर्धारण और स्वीकार किए गए कर के बीच के अंतर पर प्रोत्साहन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

7. यह प्रोत्साहन सुविधा लघु/बड़े/मध्यम उद्योगों को उपलब्ध कराई जाती है और बिहार वैट के तहत भुगतान किए गए कर के विवरण के आधार पर, जैसा कि अनुलग्नक-III के अनुसार राज्य सरकार से जारी पास बुक में दर्ज और सत्यापित किया गया है, उद्योग निदेशक को 10 साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, जिसे सरकार के खाते में जमा की गई स्वीकृत वैट राशि के खिलाफ 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति भी कहा जाता है, बशर्ते कि अधिकतम सब्सिडी पूंजी निवेश के 300% तक सीमित हो। हमें इस बात पर जोर देना होगा कि नीति दस्तावेज में मूल प्रावधान के अनुसार, परिशिष्ट-III की पास बुक में विवरण बिहार वैट अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर के संबंध में है और प्रतिपूर्ति भी इसमें जमा की गई वैट राशि के खिलाफ है। बिहार वैट अधिनियम के तहत भुगतान किया गया कर जो सरकार के खाते में जमा किया जाता है (जोर दिया गया), वह वैट अधिनियम के तहत राजकोष में भुगतान किया गया कर है।

8. प्रवेश कर एक अलग अधिनियम के तहत लगाया जाने वाला शुल्क है, जिसका नाम है उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर

बिहार कर अधिनियम, 1993. जो राज्य के बाहर से राज्य में लाई जाने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर की बात करता है। अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर माल पर राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर लगाया जाता है, और यह उसी माल या आयातित माल से निर्मित माल की बाढ़ की बिक्री पर लगाए गए वैट से अलग और भिन्न है; जो बाढ़ में शुल्क को इस हद तक सक्षम बनाता है कि प्रवेश कर का भुगतान किया गया। **जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (2017) 12 एस. सी. सी. 1**, नौ न्यायाधीशों का संविधान, पीठ ने बहुमत से प्रवेश कर के उद्ग्रहण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए पाया कि इस उद्ग्रहण को केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 304 (ए) के अनुसार गैर-भेदभावपूर्ण होने के अधिदेश को पूरा करना होगा। इसके प्रतिपूरक कर होने के सिद्धांत को औचित्य नहीं माना गया था; यह सिद्धांत कानूनी रूप से असमर्थनीय और त्यागने योग्य माना गया था। इसे गैर-भेदभावपूर्ण मानने के लिए परीक्षण केवल सत्यापित करने के लिए था: (i) क्या राज्य के भीतर निर्मित समान वस्तुएं भी इस कर के अधीन हैं और (ii) राज्य के भीतर निर्मित या उत्पादित वस्तुओं और आयातित वस्तुओं के बीच उस गिनती में कोई भेदभाव नहीं है।

9. प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत कर का प्रभार, राज्य के भीतर उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र में अनुसूचित वस्तुओं के प्रवेश पर निर्दिष्ट दरों पर कर लगाता है। धारा 3 (1) का दूसरा प्रावधान, जो उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित वस्तुओं का आयात करने वाले आयातक को ऐसे कर से केवल तभी छूट प्रदान करता है जब वह यह साबित करने का भार वहन कर ले कि ये वस्तुएं राज्य के भीतर उपभोग, उपयोग या बिक्री के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए लाई गई थीं। धारा 3 की उप-धारा (2) के अनुसार, वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करना प्रत्येक व्यापारी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनिवार्य है; जो बिहार राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में अनुसूचित वस्तुओं का आयात करता है, चाहे वह स्वयं के खाते से हो या अपने मालिक के खाते से, या

ऐसी वस्तुओं की डिलीवरी लेता है या डिलीवरी लेने का हकदार है, वह भी प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

10. धारा 3 (2) का दूसरा परंतुक इस प्रकार पढ़ा जाता है -

“बशर्ते कि जहां अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अनुसूचित वस्तुओं का कोई आयातक, बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-14 के तहत निर्दिष्ट दर पर, आयातित अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री या ऐसी आयातित अनुसूचित वस्तुओं का उपभोग करके निर्मित वस्तुओं की बिक्री के आधार पर कर देयता वहन करता है, तो बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) के तहत उसकी कर देयता इस अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम हो जाएगी:”

11. उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक में प्रावधान है कि अनुसूचित वस्तुओं के आयातक द्वारा प्रवेश कर का भुगतान करने पर, जो वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है, वैट देयता प्रवेश कर अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम हो जाएगी। उक्त प्रावधान, आयातित वस्तुओं पर उसी रूप में या किसी भी परिवर्तित रूप में राज्य के भीतर बेचे जाने पर, वैट अधिनियम के तहत कर देयता को आकर्षित करने के लिए वैट दायित्व के खिलाफ एक सेट-ऑफ को सक्षम बनाता है।

12. इस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, नीति की व्याख्या की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने राज्य के भीतर एक लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना की है और याचिकाकर्ता राज्य के बाहर से माल प्राप्त करता है और इसके आयात पर राज्य में प्रवेश करने पर प्रवेश कर का भुगतान करता है। याचिकाकर्ता वस्तुओं का निर्माण करता है या आयातित वस्तुओं को बेचता है, जो वैट दायित्व को आकर्षित करता है; जिसके खिलाफ प्रवेश कर के भुगतान के लिए एक सेट-ऑफ प्रदान प्रदान किये जाने का पात्रता है। हम एक बार फिर इस बात पर जोर देते हैं कि प्रवेश कर और वैट का शुल्क और उद्ग्रहण दो अलग-अलग मानकों के तहत है और प्रवेश कर लगाने वाले कानून में भुगतान किए गए प्रवेश

कर के भुगतान के लिए एक सेट-ऑफ का प्रावधान किया गया है; जब वह माल जिस पर प्रवेश कर लगाया गया है, उसी रूप में या किसी अन्य रूप में, बाद के लेनदेन के अधीन होता है, जो वैट दायित्व को आकर्षित करता है। इसलिए, जब वैट देयता आकर्षित होती है, तो सेट-ऑफ के बाद, निर्धारित राज्य के खजाने में केवल शेष वैट घटक का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है; जो बिहार वैट अधिनियम के तहत भुगतान किया गया कर है और सरकार के खाते में जमा किया जाता है। यह करदाता द्वारा देय बाध्य कर है, जिसे 2006 की नीति द्वारा लाए गए वैट पर सब्सिडी/प्रोत्साहन के अनुसार 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

13. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य (2018)

1 एस. सी. सी. 242 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश कर के निर्धारण पर विचार किया था जब आयातित वस्तुओं पर आगे की कर देयता (वैट) दायित्व का सामना नहीं करना पड़ा, जो बिहार राज्य के भीतर आयातक के हाथों में ही नहीं थी। करदाता राज्य के बाहर से कच्चे तेल का आयात करता था और राज्य के भीतर अपनी रिफाइनरी में उच्च गति वाले तेल, पेट्रोल आदि का निर्माण करता था, जिसे अन्य तेल विपणन कंपनियों (ओ. एम. सी.) को बेचा जाता था, जो बदले में इसे खुदरा विक्रेताओं को या अपने स्वयं के पेट्रोलियम आउटलेट के माध्यम से अंतिम उपभोक्ताओं को बेचते थे, जिसकी बिक्री आयातक द्वारा भी प्रभावित होती थी। बिहार वित्त अधिनियम, 2005 के तहत जारी एक अधिसूचना के आधार पर ओ. एम. सी. को की गई बिक्री पर कर नहीं लगाया गया, जिसमें खुदरा विक्रेताओं और अंतिम उपभोक्ताओं को बिक्री के बिंदु पर कर लगाने का मुद्दा स्थानान्तरित कर दिया गया था। उसमें करदाता बिहार वैट अधिनियम के तहत एक पंजीकृत विक्रेता होने की पहली शर्त को पूरा करता था और दूसरी, माल के आयातक होने का। लेकिन यह तीसरी शर्त को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि ओ. एम. सी. को अपनी बिक्री पर वैट का भुगतान करने की कोई देयता नहीं थी, और चौथी शर्त, चूंकि जिस बिक्री पर वैट अधिनियम के तहत

शुल्क लगाया गया था, वह किसी अन्य ओएमसी द्वारा की गई थी।

14. माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 13 में ऐसा अभिनिर्धारित किया, जिसे यहाँ निकाला गया है:-

"13. चूँकि विचाराधीन भुगतान प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 (2) की व्याख्या पर निर्भर करता है, इसलिए शुरुआत में यह बताना आवश्यक है कि उक्त प्रावधान के तहत भुगतान करने के दावे के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है:

(i) सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, धारा 3 (2) के तहत ही, प्रवेश कर के रूप में देय कर का भुगतान केवल वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक विक्रेता द्वारा किया जा सकता है।

((ii) छूट केवल तभी दी जा सकती है जब करदाता अनुसूचित वस्तुओं का आयातक हो, जो वैट अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो।

((iii) करदाता को वैट अधिनियम की धारा 14 के तहत निर्दिष्ट दरों पर कर देयता वहन करनी चाहिए;

(iv) यह केवल आयातित अनुसूचित वस्तुओं की बिक्री के आधार पर होना चाहिए; और

(v) वैट अधिनियम के तहत "उसकी" कर देयता तब अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम हो जाएगी।

15. इसलिए सेट-ऑफ केवल तभी लागू होता है जब आगे की बिक्री की जाती है, जब माल पर वैट दायित्व होता है। इस नीति का यह कभी भी इरादा नहीं था कि किसी निवेशक द्वारा भुगतान किया गया प्रवेश कर सब्सिडी का हकदार होगा; (i) क्या आयातक वैट देयता खिलाफ सेट-ऑफ का हकदार है या (ii) जब आयातक पर वैट अधिनियम के तहत कोई और दायित्व नहीं होता है, जिसमें से बाद वाले पर निश्चित रूप से दावा नहीं किया जा सकता है। बाद की बात को बहुत स्पष्ट करने के लिए, एक उदाहरण उपयुक्त होगा,

जहाँ तक, वैट अधिनियम के तहत पंजीकृत निवेशक, राज्य के बाहर से एयर कंडीशनर खरीद रहा है; जिसे उसके कारखाने में लगाया जाना है। यह राज्य में प्रवेश करने पर प्रवेश कर के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन वैट अधिनियम के तहत इसका कोई दायित्व नहीं है, जो किसी भी सेट-ऑफ को वंचित कर देगा, और इस तरह के प्रवेश कर की 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में किसी भी प्रोत्साहन का कोई सवाल ही नहीं है।

16. जहाँ तक निवेशक, जो उपभोग या बिक्री के लिए राज्य में माल लाता है, जब माल, उसी रूप में या निर्मित रूप में, राज्य के भीतर वैट देयता का सामना करता है, तो निवेशक/आयातक ई. टी. अधिनियम की धारा 3 (2) के दूसरे प्रावधान के आधार पर, आयात पर भुगतान किए गए प्रवेश कर के एक सेट-ऑफ का हकदार है। ई. टी. अधिनियम की धारा 3 (2) का दूसरा परंतुक, निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर केवल सेट-ऑफ के रूप में एक रियायत घोषित किया गया है, न कि एक शुल्क अनुभाग या एक उपाय के लिए **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (सुप्रा) में कर चोरी को रोकने के लिए कोई शुल्क लगाने वाला खंड या उपाय। इसमें है यह भी स्पष्ट रूप से माना गया है कि प्रवेश कर और वैट दो अलग-अलग कर, दो अधिनियमों के तहत; जिनमें से एक, ई. टी. अधिनियम, चार शर्तों के पूरा होने पर वैट के सेट-ऑफ की अनुमति देता है।

17. इस संदर्भ में हम **सी. सी. ई. बनाम नेशनल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (1972) 2 एससीसी 560**. का भी उल्लेख करेंगे जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'लेवी' और 'मूल्यांकन' शब्दों में अंतर किया था। उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए शुल्क और मूल्यांकन के समीकरण में त्रुटि पाई गई, जबकि यह मानते हुए कि 'यद्यपि' लेवी 'शब्द का अर्थ' मूल्यांकन 'की तुलना में व्यापक प्रतीत होता है, जिसमें यह शामिल है, फिर भी, हमें ऐसा नहीं लगता कि इसका विस्तार' संग्रह 'तक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 265 'लेवी' और 'संग्रह' (एस. आई. सी.- पैरा 19) के बीच अंतर करता है। **सोमैया ऑर्गेनिक्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम यू. पी. राज्य; (2001) 5 एस. सी. सी. 519** में भी यह

माना गया कि कर निर्धारण कानून में, 'लेवी' और 'संग्रह' शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं हैं; जबकि 'लेवी' का अर्थ कर का आकलन या कर लगाना या वसूलना है, अनुच्छेद 265 में 'संग्रह' का अर्थ लगाए गए उस कर की भौतिक प्राप्ति है। यह केवल वैट की भौतिक प्राप्ति है जिसे 2006 की नीति के तहत प्रोत्साहन/सब्सिडी की अनुमति है।

18. सी. सी. ई. बनाम वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड (1996) 3 एससीसी 434 में, यह प्रश्न उठा कि क्या इस तरह के अधिरोपण से पहले निर्मित वस्तुओं पर लगाया गया विशेष उत्पाद शुल्क लागू होगा; माल को हटाने के समय, क्योंकि शुल्क हटाने के चरण तक स्थगित था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि ' हटाने के चरण में संग्रह का विचार सुविधा के लिए तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि शुल्क हटाने के चरण में है; यह केवल हटाने के चरण में किया गया संग्रह है (एस आई सी - पैरा 5) ।' । उपरोक्त निर्णय का पालन - **पीके री-रोलिंग मिल्स (पी) लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त; (2007) 4 एस. सी. सी. 30**, में किया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'संग्रह 'और' लेवी 'अलग हैं और' संग्रह " लेवी 'का एक आवश्यक पहलू नहीं है। हालांकि, संग्रह कभी-कभी कर के वैध शुल्क का संकेत हो सकता है, लेकिन यह तार्किक रूप से इस बात का पालन नहीं करता है कि संग्रह की अनुपस्थिति का मतलब देयता का अभाव है। यहाँ, 2006 की नीति के तहत वैट अधिनियम के तहत देयता लगाई गई लेवी है, लेकिन देय राशि, जो प्रोत्साहन/सब्सिडी को सक्षम करती है, भुगतान किए गए प्रवेश कर को निर्धारित करने के बाद होती है।

19. हम एक बार फिर 2006 की नीति के खंड 2 (vi) में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों को देखते हैं, जो वैट अधिनियम के तहत भुगतान किए गए कर का विवरण एक पास बुक में दर्ज करना है, जिसका सत्यापन वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सरकार के खाते में जमा की गई स्वीकृत वैट राशि के 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है। हमें इस बात पर

जोर देना होगा कि प्रोत्साहन/सब्सिडी लेवी या कर की देनदारी पर नहीं दी गई है। यह वैट के रूप में सरकार के खजाने में भुगतान किया गया कर है जिसे 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के रूप में सब्सिडी दी जाती है। प्रवेश कर अधिनियम के तहत भुगतान की गई राशि से वैट देयता कम हो जाती है, लेकिन प्रोत्साहन केवल सरकार के खजाने में भुगतान किए गए उत्पादन कर को प्रोत्साहन/सब्सिडी के रूप में 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान करने में सक्षम बनाता है। जैसा कि उपरोक्त उद्धृत निर्णयों में पाया गया है, लेवी का आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि इसकी अदायगी है।

20. जहां तक स्पष्टीकरण का संबंध है, यह ध्यान में रखना होगा कि मूल्यांकन के समय, अंतर-राज्य लेनदेन पर लगाया जाने वाला केंद्रीय बिक्री कर, यदि मूल्यांकन में अनुमति नहीं दिया जाता है, तो इस अस्वीकृत कर को वैट के दायित्व के साथ एक अंतर-राज्य लेनदेन के रूप में माना जाएगा। इसी तरह, वैट से प्रवेश कर के रूप में दावा किए गए सेट-ऑफ के छूट में, इस आधार पर कि कुछ आयातित वस्तुओं पर वैट का सामना नहीं करना पड़ा था; दावा किए गए प्रवेश कर की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे वैट देयता में वृद्धि होगी। ये परिवर्धन, स्व-मूल्यांकन पर निर्धारिती द्वारा दाखिल किए गए विवरणी से उतने ही अलग होंगे; जो कि निर्धारित राशि होगी। इन अस्वीकृत्यों के कारण जोड़ी गई राशियाँ सब्सिडी के लिए अयोग्य होंगी, क्योंकि विभिन्न अधिनियमों के तहत निर्धारित और स्वीकृत कर के बीच की राशि का अंतर सब्सिडी के लिए योग्य नहीं होगा। भुगतान किए गए वैट के साथ भुगतान किए गए सी. एस. टी. और प्रवेश कर को दिखाने के लिए पास बुक में स्पष्टीकरण और आवश्यकता केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भुगतान किए गए वैट की 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, केवल स्व-मूल्यांकन पर वैट घटक के लिए सक्षम है जैसा कि रिटर्न में घोषित किया गया है, न कि पुनर्मूल्यांकन किए जाने पर किए गए परिवर्धन के लिए। नीति तय करने में अनुलग्नक-III में दिया गया स्पष्टीकरण और पास बुक महत्वहीन है। हमने रिटर्न पर भी ध्यान दिया है, जो निश्चित रूप से वैट देयता से बाहर

निकलने के उद्देश्य से प्रवेश कर का संकेत देता है और जो इसे भुगतान किए गए वैट का एक घटक नहीं बनाता है।

21. उपरोक्त तर्क के आधार पर, हम पाते हैं कि 2006 की नीति केवल राज्य के खजाने में भुगतान किये गए वैट पर ही प्रोत्साहन/सब्सिडी को सक्षम किया है, न कि सी. एस. टी. या प्रवेश कर पर। हम विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार करते हैं और राज्य की अपील को स्वीकार करते हैं।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

पार्थ सारथी, न्यायाधीश: मैं सहमत हूँ।

(पार्थ सारथी, न्यायाधीश)

शारुन/-

खंडन (डिस्क्लेमर) - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।